

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 400/2018

कैलाश चन्द्र गुप्ता

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सहायक शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.04.2018

आदेश की दिनांक : 11.08.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.12.2017 व 28.03.2018 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी से कोई वसूली न की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 26.02.1981 के द्वारा शीघ्र लिपिक के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 31.08.2005 द्वारा कार्यभार संभालने की दिनांक से आगामी आदेशों तक या जब तक उपरोक्त नियमों के अधीन विहित रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध कराये जाने तक के लिए जो भी पहले हो पूर्णतः अविलम्बनीय/अस्थाई रूप से निजी सचिव के पद पर वेतन श्रृंखला 10000-325-15200 में पदोन्नत किया गया। आदेश दिनांक 01.10.2005 के द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26ए के अंतर्गत निजी सचिव की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला 10000-325-15200 दिनांक 01.09.2005 को रूपये 10,000/- पर वेतन निर्धारण किया गया। आदेश दिनांक 28.09.2007 द्वारा डीपीसी के तहत अपीलार्थी को निजी सचिव के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत किया गया और तदुपरान्त

आदेश दिनांक 06.05.2013 के द्वारा डीपीसी की अनुशंसा पर शासन उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 01.09.2005 को पदोन्नति होने के कारण जो रूपये 10,000/- का वेतन निर्धारण किया गया था, उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बदल दिया गया, जो नियम विरुद्ध है क्योंकि लगभग 12 वर्ष पश्चात् अपीलार्थी का वेतन स्थिरीकरण बदला जाना अनुचित व अवैध है। उनका यह भी कथन है कि इस संबंध में विभाग द्वारा वित्त विभाग से भी राय मांगी गई और वित्त विभाग द्वारा टिप्पणी की गई कि अस्थाई रूप से पदोन्नति के आधार पर वेतन स्थिरीकरण को कार्मिक की पदोन्नति पर पुनः वेतन निर्धारण आवश्यक नहीं होगा अर्थात् तदर्थ पदोन्नति पर किया गया वेतन निर्धारण यथावत रहेगा। फिर भी अपीलार्थी से वेतन निर्धारण कर वसूली की जा रही है जो नियम विरुद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.12.2017 व 28.03.2018 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी से कोई वसूली न की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को निजी सचिव की अस्थाई/तदर्थ पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किया गया था और नियमित पदोन्नति उपरांत तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 20.04.2017 की अनुपालना में सेवा पुस्तिका की जांच उपरांत निजी सचिव के पद की नियमित पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किया गया और दिनांक 29.09.2007 से दिनांक 22.09.2013 तक रूपये 88,770/- का अधिक भुगतान किए जाने बाबत् वसूली निकाली गई, जो नियमानुसार उचित एवं सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 26.02.1981 के द्वारा शीघ्र लिपिक के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 31.08.2005 द्वारा कार्यभार संभालने की दिनांक से आगामी आदेशों तक या जब तक उपरोक्त नियमों के अधीन विहित रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध कराये जाने तक के लिए जो भी पहले हो पूर्णतः अविलम्बनीय/अस्थाई रूप से निजी सचिव के पद पर किया गया। आदेश दिनांक 01.10.2005 के द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26ए के अंतर्गत निजी सचिव की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला 10000-325-15200 दिनांक 01.09.2005 को रूपये

10,000/- पर वेतन निर्धारण किया गया और आदेश दिनांक 28.09.2007 द्वारा डीपीसी के तहत अपीलार्थी को निजी सचिव के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी से दिनांक 29.09.2007 से दिनांक 22.09.2013 तक रूपये 88,770/- का अधिक भुगतान किए जाने बाबत वसूली किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.08.2005 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यभार संभालने की दिनांक से आगामी आदेशों तक या जब तक उपरोक्त नियमों के अधीन विहित रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध कराये जाने तक के लिए जो भी पहले हो पूर्णतः अविलम्बनीय/अस्थाई रूप से निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 01.10.2005 के द्वारा अपीलार्थी को रूपये 10,000/- पर निर्धारित किया गया और आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.09.2006 को देय दर्शायी गई। इस प्रकार अपीलार्थी को तदर्थ पदोन्नति उपरांत डीपीसी के तहत अपीलार्थी को नियमित पदोन्नति भी निजी सचिव के पद पर दिनांक 06.05.2013 के द्वारा दे दी गई। विभाग द्वारा अतिरिक्त भुगतान के संबंध में वित्त विभाग से जो राय मांगी वह भी वित्त विभाग की टिप्पणी में पैरा क्रमांक 78 पर यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि कार्मिकों का पूर्व में आदेश दिनांक 31.08.2005 द्वारा की गई पूर्णतः अविलम्बनीय/अस्थाई रूप से की गई पदोन्नति के आधार पर किए गए वेतन स्थिरीकरण को इन कार्मिकों के डीपीसी वर्ष 2006-07 में चयनित होने पर पुनः वेतन निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए अर्थात् तदर्थ पदोन्नति पर किया गया वेतन निर्धारण यथावत रहेगा। इस प्रकार अपीलार्थी को तदर्थ पदोन्नति के समय दिया गया वेतन को अधिक भुगतान मानते हुए अपीलार्थी से आलोच्य आदेश द्वारा जो वसूली की जा रही है, वह पूर्णतः नियम विरुद्ध प्रकट होती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007 से 2013 तक की अवधि में किए गए अधिक भुगतान को लगभग 4-5 वर्षों पश्चात् वसूली किए जाने का आदेश जारी किया गया है, जो नियमानुसार एवं न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे मामलों में कार्मिकों को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :-

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following

few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

- (i) *Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).*
- (ii) *Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.*
- (iii) *Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.*
- (iv) *Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.*
- (v) *In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."*

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.03.2018 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अपीलार्थी से उक्त आदेश की पालना में कोई वसूली की गई है तो उसे नियमानुसार एवं न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए वापिस लौटाई जावे। अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 26.04.2018 की पुष्टि (confirm) की जाती है। अतः उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य